

# 'अगले वर्ष हर श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी की जायेगी'

## गौशालाओं की अनुदान राशि के लिये गौपालकों व संतों ने मुख्यमंत्री भजनलाल का आभर प्रकट किया

जयपुर, 10 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हाल में पेश किए गए राज्य के बजट में गौमाता और पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश भर में संचालित गौशालाओं तथा नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को इस वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन करने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर आयोजित आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल गौपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की थी, जिसमें गौवंश हेतु शैद, खेली निर्माण तथा दुग्ध, चारा, बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए एक लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हम आगामी वित्त वर्ष में भी दूढ़ लाख गौपालक परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। शर्मा ने कहा कि गौपालकों को और अधिक राहत देते हुए, गौपाल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी माफ करने और योजना के प्रावधानों को सरल बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान का प्रवासी भी देश-दुनिया में अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है तथा प्रवासियों ने हर जगह गौशालाएं बनायी हैं, जिससे गौसेवा के पुण्य कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान



भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर आयोजित आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा में आए संतों के साथ फूलों की होली खेली, चंग बजाकर होली के गीत गाए तथा सभी को होली की बधाइयां दीं।

■ आभार सभा से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने गौ-पूजा की तथा संत-महंतों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने सभी के साथ फूलों की होली खेली व चंग बजाकर होली के गीत गाये।

■ मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल शुरू की गई गौपाल क्रेडिट कार्ड योजना में अगले वर्ष दूढ़ लाख गौपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

करने के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' के दायरे को बढ़ाते हुए, आगामी वित्त वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी

की जाएगी। आभार सभा में आए संतों ने मुख्यमंत्री द्वारा गौ-संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए आभार जताया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ने गौसेवा का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। गत सरकार में गौ भक्तों को गौ-संरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन इस सरकार में हमारे लिए आशीर्वाद कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम से पूर्व, मुख्यमंत्री ने गौ-पूजा की तथा संत-महंतों से आशीर्वाद लिया। संतों ने मुख्यमंत्री को दुग्ध आढाकर उनका आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने उल्लासपूर्वक सभी के साथ फूलों की होली खेली, चंग बजाकर होली के गीत गाये तथा सभी को होली की बधाइयां दीं।

### हाई कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आदेश दिया गया था, वह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत, त्रुटिपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ थी। ऐसे में 25 फरवरी के आदेश के रिव्यू या उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए समय दिया जाए और इस दौरान इस खंडपीठ की ओर से गत 7 मार्च को दिए गए यथास्थिति के आदेश को जारी रखा जाए। इस पर अदालत ने कहा कि 25 फरवरी को दिया गया आदेश खंडपीठ का था और यह भी उसके समान ही खंडपीठ है। इसलिए वह उस आदेश के खिलाफ आदेश नहीं दे सकती। गौरतलब है कि मामले में प्रसंजान लेने के बाद, नगर निगम ने परकोटे के भवनों को लेकर तीन तरह की सूची बनाई थी। पहली सूची में 29 इमारतों को शामिल किया गया था, जो पूरी तरह अवैध हैं। हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ ने गत 25 फरवरी को इन इमारतों को सील करने के आदेश दिए थे। वहीं, इस खंडपीठ ने गत 7 फरवरी को मामले में अंतरिम रूप से यथा-स्थिति के आदेश दिए थे।

### न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 16 को भारत आर्यंगे

नयी दिल्ली, 10 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16-20 मार्च के दौरान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यहां बताया कि लक्सन के साथ, उनकी सरकार के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यवसायियों, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों सहित न्यूजीलैंड का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा।

प्रधानमंत्री के रूप में लक्सन की यह पहली भारत यात्रा होगी। वे 20 मार्च को वेलिंग्टन लौटने से पहले मुंबई भी जाएंगे। लक्सन 17 मार्च को मोदी के साथ भारत-न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मोदी गणमान्य अतिथि के सम्मान में दोपहर के भोजन की

■ वे 17 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत-न्यूजीलैंड संबंधों पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

मेजबानी करेंगे। वे उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 17 मार्च को अपराह्न नई दिल्ली में 10वीं रायसीना संवाद 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देंगे। वे 19-20 मार्च को मुंबई में रहेंगे, जहां वे भारतीय व्यापारिक नेताओं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लक्सन की यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से और स्थायी संबंधों को रक्षाकृत करती है। यह सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा हमारे लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को गहरा करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

# जस्टिस जॉयमाल्या बागची सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त

■ न्यायमूर्ति बागची 2011 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे तथा अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में नियुक्त थे।

■ वे 2 अक्टूबर 2031 को सेवानिवृत्त होंगे तथा मई 2031 में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।

सूर्य कांत, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के कोलेजियम ने छह मार्च को न्यायमूर्ति बागची को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशपद पर नियुक्ति की सिफारिश की थी।

न्यायमूर्ति बागची को बतौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कानून के विविध क्षेत्रों में 13 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त है। उन्हें जून 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जनवरी 2021 में उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया और फिर नवंबर 2021 में उन्हें

सूर्य कांत, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के कोलेजियम ने छह मार्च को न्यायमूर्ति बागची को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशपद पर नियुक्ति की सिफारिश की थी।

### '1247 शराब की दुकानों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गुटबाजी (कटिलाइजेशन) को रोकना था। उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में कई व्यवसायी मिलकर शराब की दुकानों के 'क्लस्टर' में कुछ दुकानों को खरीदते नहीं थे, जिससे पूरे 'क्लस्टर' की दरें गिर जाती थीं, और राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती थी। उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ दुकानें, जो नहीं बिकी होती थीं, उन दुकानों से गैरकानूनी तरीके से शराब बेची जाती थी, और राज्य सरकार को राजस्व में और भी हानि होती थी। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई नीति में 70 प्रतिशत "रिन्यूअल" की शर्त लगाई है। उन्होंने अदालत को बताया कि नई नीति के अनुसार, किसी भी जिले में अगर 20 प्रतिशत शराब की दुकानें नीलामी में पुराने व्यवसायियों ने ही खरीदी हो, तो इनको बची हुई दुकानें खरीदने का विकल्प दिया जाता है, ताकि ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो कि कुछ दुकानें अनबिकी रह जाएं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 11 मार्च को होने वाली दुकानों की नीलामी पर रोक से इनकार दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता भी नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं।

# वानुआतू प्रधानमंत्री ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द किया

नई दिल्ली, 10 मार्च। वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को पूर्व आर्पीएन प्रमुख और भण्डाई ललित मोदी को जारी वानुआतू पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया है। रिपोर्टों और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक कथित प्रेस विज्ञापन के अनुसार प्रधानमंत्री नापत ने कहा कि हालांकि जांच में कोई अपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इतर होल में उन्धरे बनाया गया कि इंटरपोल ने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण ललित मोदी पर अलर्ट जारी करने के भारतीय अनुरोधों को दो बार अस्वीकार कर दिया है।

प्रेस विज्ञापन में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है, मैंने नागरिकता आयोग को वानुआतू पासपोर्ट को रद्द करने की कार्यवाही तुरंत शुरू

■ प्रधानमंत्री जोथम नापत ने कहा कि वानुआतू का पासपोर्ट एक विशेषाधिकार है, न कि नागरिकता के लिए वैध कारण दिखाए जा सकें।

■ प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने नागरिकता आयोग को मोदी के वानुआतू पासपोर्ट को रद्द करने की कार्यवाही तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है।

करने का निर्देश दिया है। इस तरह की कोई भी चेतावनी ललित मोदी के नागरिकता आवेदन को स्वतः ही अस्वीकार कर दिया है।

उन्होंने कहा है कि वानुआतू का पासपोर्ट एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार, और आवेदकों को वैध कारणों से नागरिकता दिखानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में उनकी सरकार ने निवेश कार्यक्रम के

माध्यम से अपने देश की नागरिकता के लिए उचित प्रक्रिया को मजबूत किया है। बयान में कहा गया है कि अधिनियम प्रक्रिया में इंटरपोल सत्यापन सहित ट्रिपल-एजेंसी जांच शामिल है। वानुआतू दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है। इसमें 83 द्वीपों का एक द्वीपसमूह शामिल है, जिनमें से 65 पर लोग रहते हैं।

यरूशलम, 10 मार्च। इजरायल ने रविवार को घोषणा की कि वह हमास पर बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव डालने के लिए गाजा पट्टी की बिजली आपूर्ति बंद कर रहा है। इजरायली ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने एक वीडियो बयान में कहा, मैंने अभी-अभी गाजा को बिजली की आपूर्ति तुरंत रोकने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य हमास पर उन लोगों को रिहा करने का दबाव बनाना है, जो अब भी गाजा में बंधक हैं। इजरायली आंकड़ों के अनुसार, अब भी 59 बंधक हमास की कैद में हैं, जिनमें से लगभग 24 के जीवित होने का अनुमान है। कोहेन ने कहा, हम सभी बंधकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेंगे और गारंटी देंगे कि हमास (युद्ध)

# बंधकों की रिहाई के लिये इजरायल ने गाजा की बिजली बंद की

■ इजरायल के अनुसार, अब भी 59 बंधक हमास की कैद में हैं, जिनमें से 24 के जीवित होने का अनुमान है।

के अगले दिन गाजा में नहीं रहेगा। ऊर्जा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से जारी किए गये एक पत्र में देश के स्वामित्व वाली इजरायल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन को गाजा को बिजली की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया। उनके प्रवक्ता ने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा।

गौरतलब है कि इजरायल ने दो मार्च को इजरायल-हमास युद्ध विराम का पहला 42-दिवसीय चरण

समाप्त होने के साथ ही गाजा में खाद्य सामग्री सहित सहायता शिपमेंट को रोक दिया है।

हमास के अधिकारी तीन-चरण वाले युद्ध विराम के कार्यान्वयन पर नजर के लिए मिश्र और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमास ने गाजा पट्टी में बिजली आपूर्ति बंद करने के इजरायल के फैसले को 'सच्चा ब्लैकमेल' और गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते का 'उपग्रह उल्लंघन' करार दिया है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल-रिशके ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा, बिजली आपूर्ति में कटौती, क्राइसिंग बंद करना, सहायता, राहत और ईंधन के प्रवेश को रोकना और हमारे लोगों को भूखारखना सामूहिक दंड देने का प्रयास है, जो एक पूर्ण अपराध है।

### जेईएन भर्ती पेपर ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पर्याप्त सबूतों का अभाव है। मामले में पेश चार आरोप पत्रों में भी उसका नाम नहीं है। इसके अलावा, सह आरोपियों के बयान के अतिरिक्त याचिकाकर्ता से ऐसी कोई सामग्री बरामद नहीं हुई, जिससे यह साबित हो सके कि वह जेईएन परीक्षा का पेपर लीक करने और उसे वितरित करने में सीधे तौर पर शामिल था। ऐसे में सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड याचिकाकर्ता की जमानत को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिकारता वीआर बाजवा ने अदालत को बताया कि मामले में साल 2020 में एफआईआर की सुनवाई पूरी होने से 29 फरवरी, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इन चार सालों में जांच जारी रही और कई लोगों के खिलाफ कुल पांच आरोप पत्र पेश हुए। ये सभी आरोप पत्र उसकी गिरफ्तारी से पूर्व पेश हुए थे और इनमें जांच लंबित रखने वाले आरोपियों की सूची में भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। याचिकाकर्ता की भूमिका को लेकर जांच एजेंसी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है। याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ पेश आरोप पत्र में दर्ज नहीं गवाह हैं। इसलिए मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य सह आरोपियों से मिला हुआ है। आरोपी ने परीक्षा से पूर्व पेपर को परीक्षास्थलों तक पहुंचाया। इसीके अलावा याचिकाकर्ता का पेपर लीक के मामले का लंबा इतिहास रहा है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

# बम की धमकी के कारण एयर इण्डिया का विमान वापस लौटा

मुंबई, 10 मार्च। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले एयर इंडिया के विमान (एआई119) को सोमवार को बम की धमकी के बाद बीच उड़ान से ही वापस लौटना पड़ा।

एयर इंडिया के बयान के अनुसार, उड़ान भरने के आठ घंटे बाद विमान के शौचालय में विस्फोट की धमकी भरा नोट मिला। बोर्डिंग 777 विमान, जिसमें 303 यात्री और 19 चालक दल के सदस्य सवार थे, अजरबैजान के ऊपर से उड़ रहा था। उसी दौरान, विमान ने अपना रास्ता बदला और मुंबई लौट आया। लैंडिंग के बाद, विमान की जांच की गई, लेकिन बाद में पता चला कि

धमकी भरा अलर्ट झूठ था। मुंबई पुलिस अधीकारी ने घटना की पुष्टि की और कहा कि यह शौचालय में पया गया एक सामान्य धमकी भरा नोट है। प्रक्रिया के अनुसार आगे की जांच जारी है।

एयरलाइन के अनुसार, अब विमान 11 मार्च को सुबह पांच बजे उड़ान भरेगा।

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि संभावित सुरक्षा खतरे के बाद मुंबई लौटने का फैसला लिया गया। बयान के मुताबिक, यात्रियों को आवास, भोजन और अन्य सहायता प्रदान की गई है।

# पंजाब में किसानों ने मंत्रियों व विधायकों के घरों का घेराव किया

चंडीगढ़, 10 मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की अगुवाई में किसान आज पंजाब के सभी मंत्रियों व आप विधायकों के घरों का घेराव किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आान पर विभिन्न जय्येबंधियों ने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के नेतृत्व में सुनाम में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, दिडवा में वित्त मंत्री हरपाल चौमा, लहरागंगा में कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल के घरों के बाहर धरने दिए।

किसान नेताओं ने सरकार पर किसानों की आवाज दबाने के आरोप लगाए। किसानों की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 5 मार्च को चंडीगढ़ में आंदोलन किया जाना था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने 4 मार्च को ही किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और 5 मार्च को जब किसानों ने चण्डीगढ़ की ओर कूच किया तो पुलिस ने छापे मारकर और दीवारें लांचकर कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया।

■ किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक अधूरी छोड़ने की आलोचना की।

■ किसानों ने कहा, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की आवाज दबा रही है।

सुनाम में धरने को संबोधित करते जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा कि संघर्षों को डंडे और सत्ता के जोर से कभी नहीं दबाया जा सकता। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री किसान नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक बीच में अधूरी छोड़ दी थी। ये बैठक माताएं मौजूद थीं।

संयुक्त किसान मोर्चा के आब्धान पर किसानों ने सोमवार को मुक्तसर जिले के तीन विधायकों को कोठियों का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक बीच में अधूरी छोड़ दी थी। ये बैठक माताएं मौजूद थीं।

### अहमदाबाद-मुम्बई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सूची में डुप्लिकेट नामों का नया साक्ष्य सामने आ गया है, जो और भी ज्यादा गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है।" लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र तथा संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिये यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। ईपीआईसी में डुप्लिकेशन को लेकर कांग्रेस सहित, विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना के परिणामस्वरूप, ईसीआई ने कहा है कि "लम्बे समय से लम्बित" इस मुद्दे का समाधान अगले तीन महीनों में हो जायेगा।

सुनाम में धरने को संबोधित करते जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा कि संघर्षों को डंडे और सत्ता के जोर से कभी नहीं दबाया जा सकता। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री किसान नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक बीच में अधूरी छोड़ दी थी। ये बैठक माताएं मौजूद थीं।

संयुक्त किसान मोर्चा के आब्धान पर किसानों ने सोमवार को मुक्तसर जिले के तीन विधायकों को कोठियों का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक बीच में अधूरी छोड़ दी थी। ये बैठक माताएं मौजूद थीं।

संयुक्त किसान मोर्चा के आब्धान पर किसानों ने सोमवार को मुक्तसर जिले के तीन विधायकों को कोठियों का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक बीच में अधूरी छोड़ दी थी। ये बैठक माताएं मौजूद थीं।

सुनाम में धरने को संबोधित करते जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा कि संघर्षों को डंडे और सत्ता के जोर से कभी नहीं दबाया जा सकता। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री किसान नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक बीच में अधूरी छोड़ दी थी। ये बैठक माताएं मौजूद थीं।

### ट्रम्प के मनमर्जी वाले निर्णय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लड़ाई लड़ने के लिए कई उपायों को लागू करने का वादा कर रहे हैं। नेता चुने जाने के बाद अपने भाषण में कार्नी ने समूची लड़ाई को, यह कहते हुए, पूरी तरह से आर्थिक रूप दिया कि ट्रम्प कैनडा के साधारण परिवारों की आजीविका को लक्ष्य बना रहे हैं। इसका मतलब है कि कैनडा, अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगा सकता है, ताकि इन वस्तुओं के देश में और अधिक प्रवाह को रोकना जा सके। अमेरिका को सफलता मिलेगी, पहले बैंक ऑफ कैनडा के गवर्नर थे तथा उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक उच्च प्रोफाइल व अंतर्राष्ट्रीय रूप से सम्मानित गवर्नर थे।

पाटी का नेता चुने जाने के तुरंत, बाद कार्नी ने यू. एस. टैरिफ वॉर और आर्थिक हमलों से लड़ने की अपनी बुनियादी रणनीति निर्धारित की। कार्नी ने ट्रम्प टैरिफ के जवाब में सख्त कदम उठाने का वादा किया है। वे कैनडा के लोगों की वर्तमान अमेरिकी विरोधी भावनाओं का पहले अपनी घरेलू लड़ाई को

प्रभावी ढंग से लड़ना होगा। टुडो के नेतृत्व में, सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने चुनावी आधार को दिया था और कन्जर्वेटिव पार्टी ने धीरे-धीरे अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था। कन्जर्वेटिव पॉलिटीशियन, पियर पॉलिएव ने सत्तारूढ़ पार्टी पर यू. एस. के हमलों का सामना करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था। टुडो के समय विपक्षी पार्टी की स्थिति सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी से बेहतर हो गई थी।

तथापि, मार्क कार्नी के नए नेता बनने के बाद कन्जर्वेटिव पार्टी एक नए संघर्ष की उम्मीद कर रही है। कार्नी के ये बयान, कि वे अमेरिका से हार नहीं मारेंगे, देश भर में बहुत सराहने गए हैं और पोलिस में लिबरल पार्टी अब वापस कन्जर्वेटिव के नजदीक आ रही है।